

>

Title: Need to adopt a uniform procedure by University Grants Commission for admission of students in colleges of Uttar Pradesh.

*m10

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): भारत के विभिन्न राज्यों के स्कूलों में 22 करोड़ बच्चे पढ़ने जाते हैं जिसमें केवल 40 प्रतिशत बच्चे 12वीं बलास पास करते हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1 करोड़ 40 लाख बच्चे ही कालेज स्तर तक की शिक्षा के लिए पहुंच पाते हैं केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्री ने पिछले दिनों कहा था कि सन 2020 तक देश में 30 प्रतिशत छात्र विश्वविद्यालय पहुंच जायेंगे। जबकि अभी केवल 12.4 प्रतिशत ही कालेज एवं विश्वविद्यालय स्तर तक पहुंच रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार देश में अभी 500 विश्वविद्यालय एवं 25,000 महाविद्यालय हैं, जबकि चार करोड़ 60 लाख बच्चों को कालेज की शिक्षा के लिए 800 विश्वविद्यालय एवं 45 से 40 हजार डिग्री कालेज खोलने की आवश्यकता है। आज देश में राष्ट्रीय व्यवसायिक शिक्षा एवं योजनायोजनामुखी अवसर प्रदान करने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त महाविद्यालय में कक्षा संचालन के लिए 107 छात्रों को ही मान्यता दी जा रही है जबकि प्रदेश के अन्य विश्वविद्यालयों जैसे कानपुर में 560, लखनऊ विश्वविद्यालय में 420, पूर्वांचल में 360 सीटें एवं अवध विश्वविद्यालय में 360 सीटें प्रदान की जा रही है जबकि उपरोक्त सीटों के अन्तर को समाप्त करके प्रत्येक विश्वविद्यालय की सीटों के आवंटन में यूजीसी (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग) द्वारा एकरूपता कायम करने का निर्णय लेना चाहिए। यूजीसी के इस निर्णय से देश के सभी विश्वविद्यालयों में छात्रों के प्रवेश का अधिक अवसर मिलेगा तथा एकरूपता आयेगी।